replace the Haj Committee Act of 1959, and towards this end, hopes to introduce legislation in the near future after consultations, inter-alia, with the departments concerned in the Central and State Governments.

Painting in UN Delegation Office

1747. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Entrance Hall in India's UN Delegation Office in New York has been painted;

(b) who has done the painting; and

(c) how much did this painting cost?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Shri M.F. Hussain.

(c) Expenditure on the work done, to date, is Rs. 10,96,784 (Approx.)

Regulatory mechanism for trade in Currency

1748. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether at the recent G-15 Summit meet in Jamaica, it was felt that if there was an organisation which regulated trade, it was also necessary that there should be a regulatory mechanism for trade in currency;

(b) if so, what precise consensus was. reached about the structure and functioning of contemplated mechanism for trade in currency; and

(c) what steps have since been taken in pursuance thereof?.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) and (b) During discussions pertaining to the international financial crisis, the G-15 Summit at Jamaica recommended that concrete steps should be taken to develop mechanisms and adequate rules to monitor and supervise the operations of large financial market players, including hedge funds and currency speculators. They also expressed support for measures taken to increase transparency and accountability and prudential supervision and strengthening of national financial systems. They further emphasised that in the context of undertaking reforms in the international financial architecture, an international consultative process needs to be established to ensure that both developed and developing countries have a voice in the reforms being attempted. However, no specific regulatory mechanism for trade in currency was discussed.

(c) Does not arise.

विदेशी यात्राओं के परिणाम

1749. **श्री राजूभाई ए0 परमार** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश मंत्री की हाल की विदेश यात्राओं के क्या परिणाम निकले हैं,

(ख) क्या उनकी फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांस के साथ कोई रक्षा समझौता किया गया हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) विदेश मंत्री ने 2-7 फरवरी, 1999 को जमैका तथा 20-21 फरवरी, 1999 को पाकिस्तान की यात्रा की उनकी यू के यात्रा द्विपक्षीय यात्रा थी । जमैका की उनकी यात्रा जी-15 शिखर सम्मेलन के संबंध में थी । विदेश मंत्री ने प्रधान मंत्री के प्रतिनिधिमण्डल के एक सदस्य के रूप में पाकिस्तान की यात्रा की थी । देशवार उनकी यात्राओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं,

यू0 के0 :- विदेश मंत्री ने अन्य बातों के साथ साथ द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय विकास, नाभिकीय निरस्त्रीकरण तथा अप्रसार सहित बहुत से मसलो पर बातचीत की । इन वार्ताओं से आपसी समझबूझ बढ़ी हैं तथा मई, 1998 के पश्चात् द्विपक्षीय संबंधों में जो गतिरोध उत्पन्न हो गया था इससे उबरने में मदद मिली हैं ।

जमैका :- शिखर-सम्मेलन में विकासशील देशों की हित-चिन्ता के मसलों पर गहन बातचीत हुई । जिन मसलों पर बातचीत की राई उन में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत न्यायोचित एवं सम्पर्क नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थापना की महत्ता की पुनः पुष्टि, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार, दक्षिण-दक्षिण और

अन्तरा जी-15 सहयोग तथा इन मसलों पर जी-15 जी-8 वार्ता शुरू करने की प्रत्याशा शामिल हैं । ऐसी सभा प्राथमिकताओं को नौवें शिखर सम्मेलन के अन्त में जारी संयुक्त वक्तव्य में दर्शाया गया हैं । सार्वभौमिकी-कारण तथा आर्धिक उदारीकरण और चालू वित्तीय संकट से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी सदस्य इन मसलों पर विचारों के अभिसरण को संबंर्धित करने पर सहमत थे । उन्होंने आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन का आह्वान किया ।

पाकिस्तान :- पाकिस्तान की यात्रा के दौरान दोनों प्रधान मंत्रियों ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए । यह दोनों देशों की शांति और सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम हैं । विदेश सचिवों, ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षण किए, जिसके अनुसार भारत और पाकिस्तान विश्वासोत्पादक उपाय करने के लिए एक करार करने हेतु कार्य करेंगे । एक संयुक्त विज्ञाप्ति जारी की गई जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी जैसे सहयोग के नए और महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाया गया तथा मानवीय मसलों को मंत्रीस्तर पर हल करने का निर्णय लिया गया । यह निर्णय लिया गया कि दोनों देशों के विदेश मंत्री परस्पर हित के सभी मसलों पर बातचीत करने के लिए समय-समय पर बैठक करेंगे । पाकिस्तान की सरकार और जनता के साथ शांति और मैंत्री एवं दोनोंदेशों की जनता के लाभ के लिए सहयोग का व्यापक ढांचा तैयार करने की भारत की इच्छा उच्चतम स्तर पर व्यक्त की गई । सरकार आशा करती हैं कि प्रधान मंत्री के ऐतिहासिक कदम से तथा उनके इस पुनः कथन से "कि सुरक्षित, स्थायी एवं समृद्ध पाकिस्तान भारत के हित में हैं." हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नया उध्याय जुड़ेगा ।

(ख) विदेश मंत्री ने फ्रांस की यात्रा नही की ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Acceptance of LoC as International Border

1750. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to accept the Line of Control in J&K as International Line in search of a permanent solution of Kashmir issue; and

(a) if yes, the need and justification thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Denial of Permission to US Scientists

1751. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state whether Government have taken any stand or action on the denial of permission to US scientists from attending Tata Institute of Fundamental Research (TTFR) physics seminar in India?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): GOI position is that coercive and unilateral measures, whether in the economic or technology field, are counter-productive. We do not agree with any targeted policy of denying permission to scientists which comes in the way of scientific exchange and interaction. Such measures are against the accepted practices of free movement of scientific personnel and collaboration on scientific research and development. All such cases are taken up with US Government.

Relations with Neighbouring Countries

1752. SHRI ONKAR SINGH LAKHAWAT: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken initiatives to improve and strengthen relations with neighbouring countries; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI VASUNDHRA RAJE): (a) and (b) The Government have taken a number of initiatives to improve and strengthen, relations with neighbouring countris, as detailed below: